कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिकृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां, उनका नाम "गोविन्द" तथा "आदित्य" रखा गया है ।

(ख) वर्ष 1989 (जून के अन्त तक) में आम खेती के लिए केन्द्रीय किस्म रिलीज समिति द्वारा धान की दो किस्में रिलीज तथा अधिसूचित की गई हैं ।

(ग) ये किस्में पुरानी किस्मों से 10 से 15 प्रतिशत अधिक उपज देने में समर्थ हैं । ये किस्में सूखा, कीटव्याधियों तथा रोगों के प्रति अत्यधिक सहनशील हैं तथा बारानी उपराऊं क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास

3347. **श्री अजीत जोगी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पिछले तीन वर्षों में कितने नए छात्रावासों की स्वीकृति दी गई ;

(ख) पूरे देश में स्वीकृत किए गए छात्रावासों की तुलना में इसका प्रतिशत कितना है ; और

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में इन जातियों की जनसंख्या के आधार पर इस संबंध में स्वीकृत किए जाने वाले छात्रावासों की संख्या तय कर ली गई है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रावासों की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को स्वीकृत छात्रावासों की संख्या तथा देशभर में स्वीकृत छात्रावासों की तुलना में उनकी प्रतिशतता निम्नप्रकार है :—

मध्य प्रदेश को स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	देशभर में स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	प्रतिशतता
62	544	11.39

लड़कों के लिए इसी प्रकार की योजना अभी तक नहीं बनाई गई है ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उनसे प्राप्त प्रस्तावों तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों को छात्रावास स्वीकृत किए जाते हैं ।

मध्य प्रदेश को चावल और गेहूं का आवंटन

3348. **श्री अजीत जोगी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश को आवंटित किये गए चावल और गेहूं की मात्रा कितनी है और इस राज्य को वास्तव में कितनी मात्रा उपलब्ध करायी गई थी ;

(ख) क्या खाद्यान्नों की यह मात्रा मध्य प्रदेश की कुल आवश्यकता और मांग की तुलना में बहुत कम थी ; और

(ग) इसकी आवश्यकताओं और मांग के अनुसार खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) :(क) और (ख) एक विवरण (उपाबंध) संलग्न है जिसमें मध्य प्रदेश के बारे में 1988 और 1989 के दौरान सार्वजनिक वितरण

प्रणाली के लिए चावल और गेहूं की मांग उनके आबंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आबंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं और वे केन्द्रीय पूल में स्टॉक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं ।

विवरण

1988 और 1989 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मध्य प्रदेश के संबंध में चावल और गेहूं की मांग, आबंटन और उठान

(हजार मीटर टन में)

वर्ष	मांग	आबंटन	उठान
	I. चावल		
1988	595.0	250.0	206.5
1989 (अगस्त तक)	340.0	205.0 (जून तक)	106.5
	II गेहूं		
1988	600.0	410.0	299.8
1989 (अगस्त तक)	400.0	252.1 (जून तक)	126.6

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बाल श्रमिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3349. **श्री अजीत जोगी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बाल श्रमिक कार्यक्रम के अंतर्गत कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) और (ख) जी, हां । मन्दसौर में स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत बालकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के भाग के रूप में एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है । यह परियोजना 1 मई, 1988 से आरम्भ की गई थी तथा परियोजना क्षेत्र में निम्नलिखित क्रियाकलाप किए जा रहे हैं :—

(i) बाल श्रमिकों से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन को बढ़ावा देना ।

(ii) आय/रोजगार सृजन कर्मियों के तहत बाल श्रमिकों के परिवारों को लाना ।

(iii) अनौपचारिक शिक्षा योजना के अधीन बाल श्रमिकों की अनौपचारिक शिक्षा ।

(iv) उन स्थानों पर बाल कर्मकारों के लिए विशेष स्कूल स्थापित करना जहां शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक आहार, स्वास्थ्य देख रेख आदि की व्यवस्था की जा रही है ।

(v) सामाजिक कार्यकर्ता ग्रुपों तथा अन्य साधनों से जागरूकता पैदा करना ताकि बाल श्रमिकों के अवांछनीय पहलुओं के संबंध में लोगों को शिक्षित किया जा सके तथा उन्हें विश्वास दिलाया जा सके ।

मन्दसौर में स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत बालकों की संख्या का पता लगाने के लिए परियोजना क्षेत्र में एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है । परियोजना प्राधिकारियों ने बताया है कि सर्वेक्षण के आंशिक परिणामस्वरूप उद्योग में 656 कार्यरत बालकों का पता लगा है । परियोजना के एक भाग के रूप में उद्योग में रोजगार से हटाए गए 200 बालकों के लिए 4 विशेष स्कूल स्थापित किए गए हैं ।